

giving reasons for immediate legislation by the Hooghly Docking and Engineering Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Ordinance, 1984.

### MATTERS UNDER RULES 377

- (i) Compensation to farmers of Haryana, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh whose crops have been destroyed because of breach in Bhakra Canal and non-availability of electricity to Tube-wells.

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, इस दफा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यू० पी० में ख़ास तौर से और समूचे देश के किसानों के साथ आम तौर से विशेष दुर्घटनाएं और दुर्व्यवहार हुए हैं। ख़रीफ की बुवाई के वक़्त जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में नहर भाखड़ा का काट देना, ट्यूबवैलों की बिजली न मिलना और फिर अगर थोड़ी-बहुत फसल बुवाई की जाए, तो बाजरे के बीज में लेकर नर्म और कपास का बीज मिलावटी मिलना और न मिलना। इसी तरह खाद का न मिलना और मिलावटी मिलना। जो फसल बोई गई, वक़्त पर पानी न मिलने की बिना पर, तेज भूप की बिना पर, रही किस्म के खाद और बीज की बिना पर फसल तकरीबन सूख गई। किसान भयंकर अकाल की चपट में है और अगली फसल तक किसान अपनी जीविका नहीं चला सकता।

यह ठीक है कि ऐसा कोई कानून या व्यवस्था अभी तक देश में नहीं बनाई गई, जिससे कि किसान को मदद मिले। लेकिन कभी न कभी तो यह परम्परा बनानी पड़ेगी। अगर नहीं बनाई गई, तो देश तबाह हो जाएगा। ख़ास तौर से हरियाणा को समूचे देश में सब से ज्यादा नुकसान हुआ है। एक तरह से किसान बर्बाब हो गए हैं।

केन्द्र सरकार से अपील है कि कम से कम पांच सौ करोड़ रुपए मुआवजा अगर दे सके, तो किसानों को मुआवजा दे, और अगर मुआवजा न दे सके, तो बगैर ब्याज के किसानों को कर्जा दिया जाए, ताकि किसान जिन्दा रह सकें और अगली फसल उगा सकें। नहर भाखड़ा के काटने की जिम्मेदारी जिस प्रान्त में कटे उसी की हो और जितना नुकसान आगे के किसानों का हो, उसका मुआवजा उस प्रान्तीय सरकार में लेकर दूसरे प्रान्तों के किसानों को दे।

12.14 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

- (ii) Measures needed for social and economic upliftment of women.

SHRI KAMAL NATH (Chhindwara) ; It is unfortunate that the status of women has not been properly defined in the economic and social uplift programmes. The two major indices—of literacy, where for every ten literate men there are only seven literate women, and the index of mortality—where the life expectancy of women, is five years less than that of men, women, in fact, are to be regarded as an economically weaker sections. With the slow impact of progress on the social family pattern, women's dependence on the financial support from husbands is in constant jeopardy.

In the economic and social uplift programme, the Indian women face discrimination in wage structure and financial opportunities. Whether it be the public or the private sector, women receive lesser wages than men. The tea Gardens have women earning 60 per cent of the men's wages. Job opportunities are denied to most but a small fraction of thousands of women graduating each year. It is, therefore, my contention that a series of measures should be envisaged to extend such social and economic independence to women that would enable them to be rehabilitated in our society with full justice, economic and social. The banks